VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
M
N
08 NOV 2015
SUBMITTED ... HOURS
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 636)

Name of Candidate	PREMSUKH DELU		
Medium Hindi/Eng.	HINDI	Registration Number	15301
Center	Delhi	Date	8/11/15

INDEX TABLE		
Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

Signature of Examiner

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are TWENTY questions printed in HINDI and ENGLISH.
   इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।
3. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

75, 3rd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Near Axis Bank, New Delhi – 110060

103, 1st Floor, B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi – 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

All the questions are compulsory and carry 12.5 marks each. NOT MORE THAN 200 WORDS.

1. While the judiciary should be insulated from political interference, yet the executive should have a say in its appointment in order that flawed choices do not erode its credibility. Examine in context of the decision of the Supreme Court w.r.t. NJAC.

   यद्यपि न्यायपालिका को राजनीतिक हस्तक्षेप से पृथक होना चाहिए, तथापि इसकी नियुक्तियों पर कार्यपालिका को राय देने का अधिकार होना चाहिए ताकि त्रुटिपूर्ण चयन इसकी विश्वसनीयता को नष्ट न कर सकें। एन.जे.ए.सी. के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की जांच कीजिए।

हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के निर्णय में 99वें संविधान संशोधन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं मूल ढांचे के विपरीत बताते हुए रद्द कर दिया।

वास्तव में न्यायिक नियुक्ति आयोग से न्यायधीशों की नियुक्ति हेतु तीन न्यायधीशों के केस (1981, 93, 98) के द्वारा अस्तित्व में आए कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर गठन किया गया था जो न्यायधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण संबंधी कार्य देखता।

वास्तव में कॉलेजियम सिस्टम में ~~व्याप्त~~ व्याप्त अपारदर्शिता

जवाबदेहीता का अभाव, कार्यपालिका
के आरोप लगते रहे हैं। साथ ही दुनिया
में कहीं भी न्यायाधीशों की न्यायाधीशों
द्वारा नियुक्ति नहीं होती है इस
कारण न्यायिक नियुक्ति आयोग
महत्वपूर्ण परिवर्तन था लेकिन
सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया

वास्तव में इस विरोध की
समीक्षा करें तो पाते हैं कि सभी
राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति एवं
20 राज्यों की विधायिका द्वारा
पारित कानून को सर्वोच्च न्यायालय
द्वारा अवैध घोषित करना चकित
करने वाला रहा है लेकिन साथ ही
महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सर्वोच्च
न्यायालय द्वारा कॉलेजियम में
व्याप्त अपारदर्शिता, जवाबदेहीता के
अभाव को माना तथा इस संबंध में
सुधार एवं आगे बढ़ना, के
उसमें जोड़ा है जो प्रशंसनीय

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पहल है इसे मान कौशल के कदापि भी न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच तनाव के रूप में नहीं देखना चाहिए।

इसके लिए न्यायिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है और न्यायपालिका लोगों की इच्छाओं पर खरी भी उतरी है इसी तरह न्यायपालिका के कार्य इच्छा की पहल की है तथा ही इसे व्यावहारिक है इसकी जन भावनाओं का प्रतिबिम्ब है को उचित सम्मान जानी है अतः संविधान के तीनों अंगों को मिलकर काम करने में उचित हल निकालना चाहिए ताकि विधायी स्वीकार्यता बनी रहे न्यायिक स्वतंत्रता भी बनी रहे एवं सभी हितधारक एक दूसरे की नियंत्रण की भांति हो।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. What do you understand by the concept of 'Equality'? Does it imply the elimination of all differences? How does the ideal of 'Equality' differ from 'Equity'? Discuss in light of affirmative action programs in India.

'समानता' की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? क्या इसका निहितार्थ सभी अन्तरों का उन्मूलन है? 'समानता' का आदर्श 'साम्य (इक्विटी)' से किस प्रकार भिन्न है? भारत में सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों के प्रकाश में चर्चा कीजिए।

समानता का आशय है सभी व्यक्तियों की समानता। भारतीय संविधान के अनु० 14 से 18 तक समानता के मूल अधिकार का उल्लेख है लेकिन यहां ध्यातव्य तथ्य यह है कि कुछ युक्तियुक्त अपवादों का उल्लेख भी किया गया है।

अतः भारतीय संदर्भ में देखें तो समानता का आशय सभी से मात्र एकसमान व्यवहार नहीं किया जाता है अर्थात् हमारे संविधान की सामाजिक न्याय की अवधारणा के अनुरूप विशेष है मात्र विशेष व्यवहार किया जा सकता है अर्थात् महिला, बच्चे, SC

ST, OBC के सुनिश्चित कुछ प्रावधान करते है लेकिन इनका लाभ उन को विकसित या सामान्य समाज है बनाया जाता है

अतः समानता को साध्य भी समझा जा सकता है।

भारत में समानता हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यथा SC, ST, OBC आरक्षण, अनु० 17 के तहत अस्पृश्यता अंत, अनु० 18 के तहत उपाधि अंत तथा महिला और बच्चों के सुनिश्चित विभिन्न कार्यक्रम यथा समन्वित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. "Vocational skill is a great tool to usher in inclusive growth and an effective hedge against poverty". In this regard, evaluate the performance of skill development programmes in India. Discuss the problems that have been withholding their success and suggest remedies with special reference to the report of NSDA panel.

"व्यावसायिक कौशल, समावेशी विकास आरंभ करने और गरीबी को रोकने हेतु एक उत्कृष्ट उपकरण है।" इस संबंध में, भारत में कौशल विकास कार्यक्रमों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन कीजिए। इनकी सफलता को बाधित करने वाली समस्याओं की चर्चा कीजिए और एन.एस.डी.ए. पैनल की रिपोर्ट का विशेष संदर्भ देते हुए उपचार सुझाइए।

व्यावसायिक कौशल समावेशी विकास के निर्माण में महत्वपूर्ण है क्योंकि "कौशल विकास को सफल उद्यमिता की कुंजी" कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015 में माना गया है।

भारत में कौशल विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए तथा विभिन्न संस्थान यथा ITI, पोलिटेक्निक, इंजीनियरिंग संस्थान स्थापित किए गए फलस्वरूप व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त लोगों का प्रतिशत बढ़कर 4% तक पहुंचा था हाल में जारी एक रिपोर्ट में पाया गया कि कौशल शिक्षा प्राप्त युवा भी उद्योगों के अनुरूप नहीं है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अतः हम पाते हैं कि कौशल विकास कार्यक्रमों में हम कहीं न कहीं असफल रहे हैं। यदि हम इन कार्यक्रमों की असफलताओं के कारणों पर गौर करें तो हम निम्न कारण पाते हैं

(1) कार्यक्रम निर्माण तो बेहतर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन के स्तर पर कोई व्यवस्था का न होना।

(2) इन निर्माणों द्वारा केवल सरकारी नौकरी की ताक में रुचि रखना

(3) आधारभूत ढांचे का अभाव

(4) पाठ्यक्रमों एवं औद्योगिक आवश्यकताओं का कोई तालमेल न होना

(5) प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी

(6) केवल सरकारी प्रयास

अतः हाल ही में दुबारा लाई गई एन.एस.डी.P. पॉलिसी

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

हैं कि निम्न प्रयास किए जा सकते हैं

→ उचित कौशलगत विकास

→ प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की व्यवस्था

→ स्वतंत्र मूल्यांकन निकाय की स्थापना जो स्वतंत्र मूल्यांकन करे

→ पाठ्यक्रम औद्योगिक आवश्यकताओं के।

→ छात्रों को प्रेरित किया जाए उचित धनराशि उपलब्ध कराई जाए, व निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाए।

इन निर्देशों के लिए [illegible] प्रयास जैसा कौशल विकास मिशन कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. A demand to make the CAG accountable to the Parl ament has been gaining ground recently. How will this step affect the independence of CAG? What steps could be taken to strengthen CAG-PAC relatior ship?
कुछ समय से सी.ए.जी. को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। यह कदम सी.ए.जी. की स्वतंत्रता को कैसे प्रभावित करेगा? सी.ए.जी. और पी.ए.सी. के संबंधों को मजबूत करने हेतु कौन-से कदम उठाए जा सकते हैं?

CAG यानि "कम्पट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल" जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनु० 148 से 151 तक किया गया है जो भारत के वित्त का संरक्षक समझा जाता है जिसने अपनी भूमिका का बखूबी निर्वाह किया है।

CAG द्वारा सरकार द्वारा स्वीकृत बजट से खर्च होने वाले ऑडिट किया जाता है जिसमें या देखा जाता है कि खर्चा निर्धारित पद एवं प्रक्रिया से हुआ है। और इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा सदन के सामने रखते हैं

हाल में CAG को सदन के प्रति उत्तरदायी बनाने की मांग जोर पकड़ रही है जिसके कई तर्क या

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

दिया जाता है कि CAG बजट के वास्तविक परिणामों की तरफ ध्यान न देकर प्रक्रियाओं पर ज्यादा ध्यान देता है तथा प्रक्रिया के मूल का यह घोटाला मानता है जिससे देश में निकला है प्रति व्यापक असंतोष फैलता है साथ ही CAG को संसद जो जनता का प्रतिनिधि होती है के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

लेकिन इस देखते हैं साथ कदम से CAG की स्वतंत्रता का हनन हो सकता है क्योंकि इसी स्वतंत्रता के बदौलत ही 2G, कॉमनवेल्थ जैसे घोटाले उजागर हुए हैं तथा संसद के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ने से बहुमत प्राप्त दल का CAG पर दबाव बढ़ जाएगा अतः देश इस मोड़ पे सोच व्यापक विचार की आवश्यकता है।

PAC अर्थात लोक लेखा समिति CAG द्वारा जारी रिपोर्ट की जाँच करती है तथा CAG सारे मामलों

करती है दोनों के मध्य बेहतर समन्वय हेतु निम्न कदम उठाये जा सकते हैं

(1) खर्चे के बाद ऑडिट की जगह खर्चे के दौरान ऑडिट हो ताकि अपव्ययता पहले ही खत्म हो जाए।

(2) CAG और PAC में समन्वय को बढ़ाया जाए

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. The debates related to problems of higher education have been mainly limited to IITs/IIMs. However, the need of the hour is to improve 665 universities where around 30 million students are enrolled. Discuss.
उच्च शिक्षा की समस्याओं से संबंधित बहस मुख्य रूप से आई.आई.टी./आईआईएम. तक ही सीमित रहे हैं। जबकि समय की मांग 665 विश्वविद्यालयों में सुधार करने की है जिनमें लगभग 3 करोड़ छात्र नामांकित हैं। चर्चा कीजिए।

~~भारत में उच्च~~

तीव्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक राजनीतिक विकास हेतु उच्च शिक्षा का महत्व ~~निर्वि~~ निर्विवाद है लेकिन भारत में उच्च शिक्षा के संदर्भ में हम सामान्यतः IIT एवं IIM तक ही बात करते हैं जबकि सारे मात्र देश के .01% छात्र भी नहीं पढ़ते हैं। हां, यह माना कि इन संस्थानों ने ~~तकनीकी~~ तकनीकी, शोध प्रबंधन, रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है

लेकिन राष्ट्र के समावेशी, त्वरित, धारणीय विकास हेतु अन्य विश्वविद्यालयों की तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि बिना उचित ध्यान दिए हम उन

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

में उचित कौशल एवं दक्षता का विकास ही नहीं कर पाएंगे तथा बेरोजगारों की फौज खड़ी करेंगे साथ ही हमारी तथा उद्योगों के लिए कुशल श्रम शक्ति का अभाव होगा तथा हम "पॉपुलेशन डिविडेंड" से वंचित होंगे। तथा देश में आंतरिक अशांति भी पैदा होने का खतरा रहता है।

अतः हाल में सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु प्रारंभ किया गया "रूसा" अभियान तथा भारतीय संस्थानों की रैंकिंग प्रणाली भी प्रयास, कौशल विकास कार्यक्रम, इन विश्वविद्यालयों में पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, पाठ्यक्रम निर्धारण में स्वायत्तता देना साथ ही पाठ्यक्रम को आधुनिक उद्योगों के साथ सामंजस्य वाला बनाना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखो)

हेतु प्रेरित कर, हेरिटेज (वि.) विश्वविद्यालय की स्थापना बढ़ाकर, योग्य प्रोत्साहन देकर इस क्षेत्र में सुधार ला सकते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. While tribunals are responsible for adjudicating cases, which require technical expertise and specialization, they are not to be understood as a court. Elaborate. Also, discuss whether the recent rulings, such as banning mining or old diesel vehicles, are an example of overreach.
तकनीकी दक्षता एवं विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले मामलों का निर्णय करने के बावजूद न्यायाधिकरण न्यायालय नहीं समझे जाते हैं। कथन पर विस्तारपूर्वक चर्चा करें। इसके अतिरिक्त, चर्चा कीजिए कि क्या न्यायाधिकरण द्वारा खनन या पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाना अपनी सीमाओं के अतिक्रमण के उदाहरण हैं।

भारतीय न्यायपालिका के विकास में न्यायाधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन इन्हें अर्द्ध न्यायिक निकाय ही माना जाता है ये वास्तव में किसी क्षेत्र विशेष से सम्बंधित होते हैं जहां उच्च या निम्न न्यायालयों में की जगह नहीं चला विवाद अधिकरण अनु. 262 की उच्च समय एवं परिस्थितियों के अनुसार गठित किए गए हैं यथा हरित न्यायाधिकरण

जहां तक न्यायालय की निर्णय का प्रश्न है ये क्षेत्र विशेष से सम्बंधित होते हैं तथा इनमें न्यायिक विशेषज्ञों के साथ साथ उस क्षेत्र के गैर न्यायिक विशेषज्ञ व्यक्ति भी शामिल होते हैं यथा हरित न्यायाधिकरण

में पर्यावरण विशेषज्ञ

यहाँ तक न्यायाधिकरण द्वारा खनन एवं पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध का सवाल है तो उचित ही माना जाना चाहिए क्योंकि इसमें न्यायाधिकरण पर्यावरण विशेषज्ञों से भी परिपूर्ण है साथ ही इसके गठन उद्देश्य भी पर्यावरणीय मामलों की तेजी से सुनवाई का पर्यावरण निर्धारण को कर अगर हम देखें तो हाल में हरित न्यायाधिकरण द्वारा दिल्ली में 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों, मैटिरियल, रोहतांग दर्रे में डीजल वाहनों पर रोक उल्लेखनीय है

चूँकि स्वयं भारत सरकार ने "राष्ट्रीय निर्धारित कटौती योगदान" के तहत 33-35%. कटौती का वादा किया है तो हम कह सकते हैं ये कदम आवश्यक है

लेकिन साथ ही ऐसे कम निर्णय

में लोगों की आजीविका एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का भी ध्यान रखना होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The 2nd generation reforms vital for the development of the nation are contingent upon the states as most of them fall in the concurrent list. Discuss with examples.

राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने वाले दूसरी पीढ़ी के सुधार राज्यों पर निर्भर हैं क्योंकि उन सुधारों से संबंधित अधिकतर विषय समवर्ती सूची में आते हैं। उदाहरण के साथ चर्चा करें।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Discuss, with examples, the role of Civil Society in making governance citizen centric. What are the factors that are hindering their growth in developing countries, like India?
शासन को नागरिक केंद्रित बनाने में नागरिक समुदाय (सिविल सोसायटी) की भूमिका पर उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। वे कारक कौन-से हैं जो भारत जैसे विकासशील देशों में इनकी वृद्धि को बाधित कर रहे हैं?

शासन को नागरिक केन्द्रित बनाने में सिविल सोसायटी की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि एक जागरूक सिविल सोसायटी प्रशासनिक ढांचे में फैले व्यापक भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, अपारदर्शिता, गोपनीयता, और निरंकुशता व्यवस्था में परिवर्तन ला सकती है।

सिविल सोसायटी की भूमिका को एक अरुणा राय द्वारा स्थापित MKKS नामक NGO द्वारा चलाए गए जन सुनवाई कार्यक्रम के रूप में देख सकते हैं जिसने ग्रामीण राजस्थान में भ्रष्टाचार को लेकर व्यापक जागरूकता और साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को अपने रवैये में भी परिवर्तन करवाया

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत जैसे देश में सिविल सोसायटी के विकास को बाधित करने वाले कारक निम्न हैं :-

(1) देश में व्यापक पैमाने पर फैली गरीबी, अशिक्षा, रूढ़िवादिता के कारण से नागरिक उचित मांग नहीं कर पा रहे हैं।

(2) व्यापक जन जागरूकता का अभाव भी इसके विकास में बाधक है

(3) सरकार तथा सरकारी अमले का इन संगठनों को हतोत्साहित करने के विभिन्न प्रयास जिनमें हरियाणा RTI कार्यकर्ताओं की हत्या तक करवा दी जाती है।

(4) समाज सुधारकों की हत्याएं उदा० नरेन्द्र दाभोलकर

(5) पंजीयन नियमों की जटिलता तथा विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस तरह हम देखते है अनेक कारणों से भारत विकास नहीं हो पा रहा है अतः ओपर व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली में उचित कारणों द्वारा भारत विकास का लोकतंत्र के कल्याणकारी राज्यों के लक्ष्य को बढ़ावा दिया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. The passing of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015 marks a significant step towards reforming the mining sector. Discuss its salient features along with highlighting the apprehensions against the act. Further analyse the role of District Mineral Foundation in ensuring equitable benefit for all.

खान और खनिज (विकास एवं नियमन) संशोधन विधेयक, 2015 का पारित होना, खनन क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का संकेत देता है। अधिनियम के विरुद्ध व्यक्त की गई आशंकाओं को उजागर करने के साथ-साथ इसकी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। साथ ही, सभी के लिए समान लाभ सुनिश्चित करने में जिला खनिज फाउंडेशन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस हाशिए में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Discuss the role of PESA as an effective tool in ensuring participative democracy and development of the tribal people. Also, examine the reasons for its poor implementation.
सहभागी लोकतंत्र और जनजातीय लोगों का विकास सुनिश्चित करने में एक प्रभावी उपकरण के रूप में पी.ई.एस.ए. की भूमिका की चर्चा कीजिए। साथ ही, इसके खराब कार्यान्वयन के कारणों की जांच कीजिए।

73 वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप लाए गए त्रिस्तरीय पंचायती राज को भारतीय संविधान की 5वीं एवं 6वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया था इन क्षेत्रों की अपनी विशिष्टताओं को देखते हुए 1996 में पैसा अर्थात "पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़ एक्ट" लाया गया ताकि इन क्षेत्रों में सहभागी स्वशासन लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को लागू किया जा सके।

चूँकि जनजातीय समाजों की अपनी विशिष्टताओं, परम्पराओं के कारण अपनी एक अलग पहचान रखते थे अतः इन क्षेत्रों में पंचायती राज को ज्यों का त्यों लागू नहीं किया जा सकता था साथ ही इन क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएँ थी।

इस दिशा में पेसा एक्ट महत्वपूर्ण रहा है जिसने इस लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित कर पाए तथा इन क्षेत्रों में इस कानून के तहत व्यापक स्वायत्तता प्रदान की गई तथा ग्राम सभा को शक्तिशाली बनाया गया तथा प्राकृतिक संसाधनों के खनन हेतु पहले इन ग्राम सभा से मंजूरी लेना आवश्यक है तथा प्राप्त रायल्टी से स्थानीय विकास का कार्य किया जाता है. लोगों द्वारा अपने विकास की प्राथमिकताओं को स्वयं तय किया जाता है।

लेकिन हम देखते है कि जिन उद्देश्यों को लेकर पेसा कानून लाया गया था उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में निम्न कारणों से सफल नहीं हो पा रहा है

1) अशिक्षा : इन क्षेत्रों में व्यापक रूप अशिक्षा फैली हुई है साक्षरता दर बहुत कम था

2) गरीबी: गरीबी के कारण भी उचित क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है

3) सरकारी हस्तक्षेप: अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप के कारण से निष्पक्ष ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सरकारी अधिकारियों की उदासीनता भी इसकी असफलता का कारण बनती जा रही है साथ ही और परम्परागत खतरे जैसे तस्करी, आतंकवाद, नक्सलवाद इत्यादि के कारण से निकाय ठीक से कार्य नहीं कर पा रही है।

अतः इन लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण हेतु सरकारी अधिकारियों की मनोवृत्ति परिवर्तन, उचित वित्तीय अनुदान, शिक्षा का विस्तार करके, स्वायत्तता प्रदान करके, चुने हुए प्रतिनिधियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करके, महिलाओं के सशक्तिकरण से हम लोकतांत्रिक जड़ों को धरा पर गहरा रोप सकते हैं।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. What do you mean by lifestyle diseases? What are the factors leading to the increased occurrence of lifestyle diseases in India? Discuss their impact on the economic conditions of the individuals and productivity of the economy.
जीवन शैली (लाइफ स्टाइल) जनित रोगों से आप क्या समझते हैं? भारत में जीवन शैली संबंधी रोगों को बढ़ाने वाले कारक कौन-से हैं। व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति और अर्थव्यवस्था की उत्पादकता पर उनके प्रभाव की चर्चा कीजिए।

जीवन शैली जनित रोगों से आशय है अपने जीवन जीने के तरीकों द्वारा पैदा हुए रोग अर्थात, अपनी दिनचर्या, खानपान, रहन सहन इत्यादि से पैदा रोग यथा॰ मधुमेह, उच्च रक्तचाप, इत्यादि

भारत में जीवन शैली संबंधी रोगों को बढ़ाने वाले कारक निम्न हैं:-

(1) खानपान: आज आधुनिक जीवन में व्यक्ति उचित समय पर खाना नहीं खा पाता है पुनः वह डिब्बाबंद खाने पर अत्यधिक निर्भर है फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है।

(2) दिनचर्या: आधुनिक युग में मनुष्य की दिनचर्या बुरी तरह से गड़बड़ा गई है फलस्वरूप वह समय पर सोना, खाना पीना नहीं कर पाता है

(3) तनाव : बढ़ते भौतिकतावाद एवं अकेलेपन व अधिकतर समय इलेक्ट्रोनिक मेग्रो के साथ कार्य करने के कारण वह बुरी तरह तनाव में रहता है फलस्वरूप वह उच्च रक्तचाप जैसे रोगों से ग्रस्त हो जाता है।

(4) मिलावट : बाजार में अधिकतर खाद्यान्नों में मिलावट की रही है जिसे हम लोकप्रिय उत्पाद मैगी के संदर्भ में देख सकते हैं।

एक राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है की मानव निरोग स्वस्थ हो क्योंकि यदि मानव विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त होगा तो वह अपनी पूर्ण क्षमता से कार्यों को संपादित नहीं कर पायेगा साथ ही उसे अपनी आमदनी का अधिकतर हिस्सा दवाओं पर खर्च करना होगा जिसके कारण वह अपनी चाहतों से महरूम होगा साथ ही सरकार को भी स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा खर्च करना होगा

होगा जिससे उनके पास विकास कार्यों हेतु धन भी उपलब्ध होगा

अतः स्वस्थ मानव ही स्वस्थ राष्ट्र बनाता है तथा देश विकास की तरफ उन्मुख होता है अतः एक बेहतर जीवन शैली जिसे व्यक्तिगत कल्याण एवं राष्ट्र कल्याण हो अपनाई जानी है जिसमें 'योग' की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

12. In a country, where one-third of the population is already economically excluded, prescribing minimum qualifications for elections to the Panchayati Raj will be the final nail in the coffin of a genuine grass-roots democracy. Discuss.

एक ऐसे देश में, जहां एक-तिहाई जनसंख्या पहले से ही आर्थिक रूप से अलग-थलग है, पंचायती राज के चुनाव हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना एक वास्तविक आधारभूत लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील सिद्ध होगा। चर्चा कीजिए।

हाल में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन हेतु शैक्षिक योग्यता का मानदण्ड एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहा है जिसे हम राजस्थान एवं हरियाणा के संदर्भ में देख सकते हैं।

इन संस्थाओं में शैक्षिक योग्यता का निर्धारण करने वाले निम्न तर्क देते हैं

(1) इन संस्थाओं में पढ़े लिखे लोग आएंगे जिनसे विकास कार्य तीव्र होंगे क्योंकि वे ऐसी जानकारी रखते हैं।

(2) भ्रष्टाचार कम होगा।

(3) जिम्मेदारी तय होगी क्योंकि जो कार्य करेगा वह भला बुरा अच्छी तरह समझेगा वह या नहीं कह सकेगा उसे तो जानकारी ही नहीं थी जब सचिव ने अंगूठा लगवा लिया।

(4) महिलाएं अधिक सक्रियता से भागीदारी निभाएगी क्योंकि वे पढ़ी लिखी होंगी।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(5) इससे साक्षरता दर बढ़ेगी क्योंकि इससे लोग स्कूल जाने को प्रेरित होंगे।

आलोचक इसके विरोध में निम्न तर्क देते हैं

(1) यह भेदभाव पूर्ण है क्योंकि ऐसा विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में नहीं है

(2) राज्य जहां महिला साक्षरता 52.1% थी वहां 48% महिला आबादी प्रत्यय साक्षरता 79% वहां 20% आबादी को चुने जाने के अधिकार से वंचित कर दिया यह लोकतंत्र की बुनियादी अवधारणा के विपरीत है।

(3) ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां पढ़े लिखे कोई अपराध नहीं करते हों

(4) लोकतंत्र की बुनियादी मांग प्रत्येक व्यक्ति को निर्णय में भागीदार बनाने के विपरीत है

अतः हम देखते हैं कि पक्ष एवं विपक्ष दोनों में ही मजबूत तर्क दिए जा सकते हैं राज० में मात्र आधार पर

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनाव हो चुके है जहां एक तरफ युवा आबादी चुन कर आई है लेकिन दूसरी तरफ गलत डिग्रियाँ भी लोगों ने लगाई है फलस्वरूप कई मामले दर्ज हुए है दूसरी तरफ हरियाणा का मामला सर्वोच्च न्यायालय में है यहां देखें पक्ष विपक्ष दोनों को देखते हुए एक उचित निर्णय लेना चाहिए जिससे लाखों लोग इन नियमों के चुनाव लड़ने से वंचित नहीं हो इस हेतु देश में एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए साथ ही लोगों को 10 वर्ष का ग्रेस पीरियड भी देना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Ever since the National Commission for Women (NCW) came into existence in 1992, its composition and functioning have been contentious and controversial. Discuss.

वर्ष 1992 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.डब्ल्यू.) की स्थापना के बाद से ही, इसकी संरचना और कार्य पद्धति विवादास्पद और विवादग्रस्त रही है। चर्चा कीजिए।

महिला अधिकारों के उचित क्रियान्वयन महिलाओं संबंधित योजनाओं, कानूनों के क्रियान्वयन, निगरानी, उचित सुझाव हेतु 1992 में गठित महिला आयोग इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

महिला आयोग में एक अध्यक्ष तथा पांच सदस्य होते हैं तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केन्द्र की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

महिला आयोग महिला अधिकार संबंधी मामलों में पीड़िता की शिकायत या स्वतः संज्ञान द्वारा मामले को अपने हाथ में ले सकती है तथा वह जांच कर सकती है क्षतिपूर्ति हेतु सिफारिश कर सकती है महिलाओं को कानूनी सलाह देती है। इस आयोग के पास दीवानी न्यायालय की शक्तियां हैं पर कोई दस्तावेज देख सकती है यहां

सकती है तथा जाँच कर सकती है लेकिन यह स्वयं दण्ड नहीं दे सकती है यह दण्ड देने की सिफारिश कर सकती है।

पिछले कुछ सालों से महिला आयोग विवादास्पद रही है हाल मामलों में हम पाए तो हम पाते हैं कि महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति सक्रिय राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों की होती है फलस्वरूप कार्यवाही राजनीतिक रूप ले लेती है जैसे हम दिल्ली महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्यों की गुवाहाटी मामले के निर्णय में देख सकते हैं।

अतः इस हेतु हमें नियुक्ति नियमों में कुछ बदलाव लाने पर गैर राजनीतिक एवं पेशेवर व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है नियुक्ति हेतु एक कमेटी बनाई जा सकती है

लेकिन महिला आयोग की कार्यप्रणाली भी विवादास्पद रही है मामलों

देखा गया है जब तक मामला मीडिया में
नहीं उछलता है महिला आयोग निष्क्रिय
रहता है पुनः महिला आयोग के पास
दण्ड देने की शक्ति नहीं है ~~अतः इसे~~ यह
केवल सिफारिश कर सकती है अतः
हमें महिला आयोग को आत्मनिर्भर
और शक्तिशाली बनाना होगा साथ
ही हमें लोगों की मनोवृत्ति परिवर्तन
हेतु भी कार्य करना होगा।

14. Discuss the importance of mid-career performance appraisal for civil servants. Also evaluate the feasibility and effectiveness of compulsorily retiring serving bureaucrats after such a review.
लोक सेवकों के लिए मिड-करियर (कार्यकाल के मध्य में) कार्य निष्पादन मूल्यांकन के महत्व की चर्चा कीजिए। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की समीक्षा के पश्चात् सेवारत नौकरशाहों के अनिवार्य अवकाश ग्रहण की व्यवहार्यता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।

मिड-करियर

हाल ही में लोक सेवकों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहा है मिड कार्यमूल्यांकन का आशय है एक निश्चित समय बाद किसी नौकरशाह के द्वारा मध्य करियर में किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन किया जा रहा है

पिछले कुछ समय से जब नौकरशाहों पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, लालफीताशाही, अपारदर्शिता, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के मामले ज्यादा सामने आए हैं साथ ही साथ भी ज्यादा देखा है PSU, ~~[illegible]~~ मिड में मिल जैसे कार्यक्षेत्रों के बावजूद हम मुखर्जी कमेटी के 10वें नम्बर पर विश्वास है तब इसकी महत्ता और बढ़ जाती है इसी प्रकार

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इससे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू, इंदिरा गांधी इत्यादि ने भी विभिन्न संस्थाओं के निष्फल होने के पीछे नौकरशाही की औपनिवेशिक मानसिकता को जिम्मेदार ठहराया था।

साथ ही इसे संविधान के सामाजिक न्याय की अवधारणा के साथ जोड़ने हेतु नौकरशाही में ~~प्रतिबद्धता~~ कार्यकुशल प्रतिबद्धता बढ़ाने हेतु, पेशेवर स्वरूप लाने हेतु, पारदर्शिता लाने हेतु, नागरिक केन्द्रित बनाने हेतु, उद्देश्य प्रशासन हेतु, दक्षता एवं कौशल को बढ़ाने हेतु, परिणामोन्मुखता लाने हेतु मिड करियर कार्य निष्पादन मूल्यांकन आवश्यक है।

इस प्रकार की समीक्षा के पश्चात अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रावधान की व्यवहार्यता एवं प्रभावशीलता की जांच तक बात करें तो यहाँ पर संविधान के प्रावधानों अर्थात अनुच्छेद 309, 310, 311 का भी ध्यान रखना चाहिए जो नौकरशाही को

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

निर्वाचित निकाय प्रदान करते हैं यदि
इन निर्वाचित कायो में राज्य नेता
होंगे तो ~~सेक~~ ईमानदार नौकरशाह
प्रेरित होंगे तथा भ्रष्ट हतोत्साहित होंगे
तथा निकायों में पारदर्शिता ~~आएगी~~
एवं जवाबदेहिता आएगी लेकिन साथ
ही हमें यहां पर यह भी ध्यान
रखना होगा कि कहीं इन प्रावधानों
का उपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थों
की पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए
अन्यथा हम spoil तंत्र की तरफ
बढ़ जाएंगे जो कि कदापि उचित
नहीं होगा।

15. The Polio eradication programme is a widely acknowledged success story with vital lessons for other immunisation initiatives as well. Highlight the challenges faced by immunisation efforts in India. In this context, what does Mission Indradhanush seek to achieve? Explain the rationale, objectives and strategies for implementation of the mission.

पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम व्यापक रूप से स्वीकृत सफलता की कहानी है। इसने अन्य टीकाकरण पहलों हेतु भी महत्वपूर्ण दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं। भारत में टीकाकरण संबंधी प्रयासों के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। इस संदर्भ में, *मिशन इन्द्रधनुष* का लक्ष्य क्या है? इस मिशन के औचित्य, उद्देश्यों और कार्यान्वयन की रणनीतियों की व्याख्या कीजिए।

भारत में 1995 में शुरू पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम विश्व के सामने एक प्रेरणाप्रद उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसके बदौलत हम 2013 को पोलियो मुक्त हो गए।

लेकिन इस कार्यक्रम की सफलता के पीछे लोगों की व्यापक भागीदारी, सिविल सोसाइटी योगदान, सरकारी कर्मियों की मनोवृत्ति, कार्यक्रम रणनीति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

जहाँ तक भारत में टीकाकरण की चुनौतियों का सवाल है यहाँ पर फैली व्यापक गरीबी, अशिक्षा, रूढ़िवादिता धार्मिक आस्था, विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, सरकारी कर्मियों की उदासीन रवैया, भ्रष्टाचार

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

~~स्वास्थ्य~~ स्वास्थ्य क्षेत्र में रोगागत अभाव, जन जागरूकता का अभाव इत्यादि महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं।

इस दिशा में हाल में शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष महत्वपूर्ण है जिसका लक्ष्य है 90% टीकाकरण करना। आज भी देश में मात्र 65% ही टीकाकरण हो पाया है प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले 2.7 करोड़ बालकों में से 16.3 करोड़ बालक अपना पांचवां जन्म दिन भी नहीं देख पाते हैं।

अतः इस योजना में लोगों को 7 बीमारियों टीटनस, काला कुकर, हिपेटाइटिस-B पोलियो, डिप्थीरिया इत्यादि हेतु यह योजना शुरू किया गया है जिसमें पहले चरण में 201 जिले शामिल किए गए हैं जो पर यह योजना ज्यादा निष्फल था है हाल में सरकार द्वारा चरण शुरू कर दिया गया है।

इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु व्यापक अभियान चलाया जा

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

रहा है जैसे सिविल सोसायटी, NGO सरकारी समितियों, स्वयंसेवकों का सहयोग लिया जा रहा है उनके गानों, कहावतों के माध्यम से जागरूकता फैलायी जाती है। तथा नियमित मॉनिटरिंग की ~~जा रह~~ जा रही है तथा फीडबैक लिया जा रहा है।

जहां तक [illegible] का सवाल है इससे हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाएंगे।

16. Promulgation of the newest constitution of the region has thrown up new challenges for the oldest constitutional democracy in South Asia. Examine India's role, concerns and dilemmas vis-à-vis the constitutional process in Nepal.
दक्षिण एशियाई क्षेत्र में एक नवीनतम संविधान के लागू होने से दक्षिण एशिया के सबसे पुराने संवैधानिक लोकतंत्र हेतु नई चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई हैं। नेपाल में संवैधानिक प्रक्रिया के विषय में भारत की भूमिका, चिंताओं और दुविधाओ की जांच कीजिए।

हाल में दक्षिण एशियाई देश नेपाल द्वारा अपना संविधान स्वीकृत किया गया जो लोकतांत्रिक विकास के सिद्धांत में महत्वपूर्ण कदम रहा। लेकिन इस संविधान के कुछ प्रावधानों के कारण वहाँ पर हुए व्यापक प्रदर्शनों के कारण भारत के सामने नई चुनौती एवं दुविधाएं पैदा हो गई हैं।

नव स्वीकृत नेपाली संविधान के कुछ प्रावधानों का वहाँ के मधेशी एवं अन्य ~~अल्प~~ अल्प संख्यक समुदायों द्वारा विरोध किया जा रहा है चूंकि मधेशी लोग तराई प्रदेश में रहते हैं तथा वे भारत से गए हुए लोग हैं अतः उनके द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन से भारत के कुछ राज्यों यथा बिहार, U.P में भी अशांति का खतरा पैदा हुआ है साथ ही एक अशांत नेपाल

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भी भारत के लिए कभी भी महत्वपूर्ण
नहीं हो सकता है नेपाल की भारत से
खुली सीमा है अतः चिंता और ज्यादा
बढ़ जाती है। पुनः मधेशियों के
हिंसक विरोध एवं घेराबंदी के कारण
नेपाल अवरुद्ध नेपाल को भारत
विभिन्न आवश्यक वस्तुओं तथा पेट्रोलियम
पदार्थों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है
फलस्वरूप वहाँ पर काफी किल्लत पैदा
हो गई है तथा नेपाल के जन द्वारा
भारत की आलोचना की है तथा चीन
से सहायता मांगी है फलस्वरूप वहाँ पर
चीन का हस्तक्षेप बढ़ सकता है जो कि
भारत के लिए चिंताजनक है।

साथ ही नेपाली राजनीतिक
दलों द्वारा अस्थिरता के कारण भारत
पर आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि
वैश्विक स्तर पर भारत की छवि
के प्रतिकूल है और विश्व पटल पर
सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट हेतु
महत्वपूर्ण दावेदार है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

साथ ही भारत के लिए पड़ोसी समुदाय
चीनी निकटता भारत के लिए महत्वपूर्ण
है तथा नेपाल भी महत्वपूर्ण अतः एक
दुविधा उपस्थित हो जाती है

अतः इन विवादों में भारतीय
नेतृत्व को उचित, शांतिपूर्ण हल
के लिए नेपाल सरकार से हल का प्रयास
करना चाहिए ताकि उचित समाधान
निकल सके। जिससे पड़ोसियों के अधिकार
भी सुरक्षित रहे। नेपाल की सफलता
की नई इबारत लिखे।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. India continues to host a large population of refugees without being a signatory to either the 1951 United Nations Refugee Convention or its 1967 Protocol. What are the reasons and implications of such a scenario? Is it time for India to reconsider its stand and become a signatory to this convention?

भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन 1951 या इसके 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता न होते हुए भी शरणार्थियों की एक बड़ी संख्या निरंतर स्वीकार कर रहा है। ऐसे परिदृश्य के कारण और निहितार्थ क्या हैं? क्या यह भारत हेतु अपने रूख पर पुनर्विचार करने और इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बनने का समय है?

भारत व्यापक रूप से वैश्विक शरणार्थियों का महत्वपूर्ण गंतव्य बना हुआ है जिसे हम बांग्लादेशियों के विषय में देख सकते हैं।

यहाँ तक इसके कारण की बात है हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं :-

(1) चूँकि भारत सदैव वैश्विक शांति का पक्षधर रहा है तथा मानव कल्याण को सर्वोच्च स्थान दिया है अतः यहाँ आने वाले लोगों को शरण दी जाती है

(2) भारत मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा करता

(3) यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम् मानवता की भावना को ध्यान में रखते हुए भारत ऐसा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

बढ़ा उठा रहा है जैसे कि हिन्दू, सिक्ख मुस्लिम शरणार्थियों के निर्णय में देखे जाते हैं

(4) नेविश्वास की धर्मनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक न्याय अवधारणा के लिए हेतु।

जहाँ तक विधियों पर अनुमोदन कोई भी बात है इसके लिए हमें भारत की परिस्थितियों को भिन्न नजर से मूल्यांकन करना होगा

(1) शरणार्थियों के कारण आज भी हमारा पूर्वोत्तर अर्थात् यहाँ पर इस समस्या के कारण जनजातीय संघर्ष, पहचान संकट आदि पैदा हो रहे हैं

(2) आज हम दुनिया के ~~सबसे बड़े~~ दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाले देश हैं अतः हमारे प्रवासियों की संख्या और बढ़ सकती है जिससे संसाधनों पर दबाव और बढ़ जाएगा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) इससे भौतिक असीमित एवं हिंसा की भावना के नए होने का खतरा पैदा हो सकता है

(4) आतंकवाद जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं

अतः इसे इस संबंध में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए तथा वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य निकायों के माध्यम से शांति बहाली का प्रयास करना चाहिए ताकि ऐसी समस्याएं कम से कम पैदा हो तथा मानवीय दृष्टिकोण से भारत इसे शरणार्थी स्वीकार तो करे चाहिए लेकिन आपदा सुरक्षा के साथ। अतः विधि या नीति और नियम बनाना चाहिए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Has India's res stance to CTBT lost relevance? Examine in view of the evolution of Ind a's policy and the changing global scenario.
क्या सी.टी.बी.टी. पर भारतीय प्रतिरोध अप्रासंगिक हो चुका है? भारतीय नीति के विकास और परिवर्तनशील वैश्विक परिदृश्य के दृष्टिकोण से कथन की जांच कीजिए।

सी.टी.बी.टी अर्थात "व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि" जिसमें सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर ~~प्रतिबंध~~ सभी जगह अर्थात नभ, थल, जल इत्यादि में रोक लगाई गई है।

भारत ने अभी तक सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि

1) भारत को भेदभाव पूर्ण मानता है क्योंकि यह P-5 को कई छूट देती है।

2) भारत के पड़ोस में चीन तथा पाकिस्तान परमाणु बम सम्पन्न हैं अतः न्यूनतम प्रतिरक्षा संतुलन आवश्यक है और साथ ही हमारा चीन से 1962, पाक से 1965, 1971, 1999 में विवाद हो चुका है अतः इनसे हमेशा खतरा बरकरार है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) भारत ने पहले से ही पहले परमाणु बम इस्तेमाल न करने की नीति घोषित कर रखी है।

(4) भारत ~~निशस्त्र~~ पूर्णतः निशस्त्रीकरण में विश्वास करता है।

अतः भारत ने अब तक इन संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जहां तक भारतीय नीति के विकास एवं परिवर्तनशील वैश्विक दृश्य की बात है भारत के लिए अब यह नीति और ज्यादा प्रासंगिक हो चुकी है क्योंकि चीन भारत को घेरने के लिए "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" की नीति अपना रहा है तथा पाक बार बार परमाणु हमले की धमकी देता है तथा हाल में अमेरिकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी परमाणु जखीरा भारत से ज्यादा एवं बढ़ता जा रहा है। पाक के पास परमाणु जखीरा आतंकवादियों के हाथ भी जा सकता है अतः इसके व्यापक तैयारी की जरूरत है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

जहाँ तक हमारी विश्वसनीयता की बात है हमारे बिना सन्धि पर हस्ताक्षर किए 2008 में अमेरिका के साथ सिविल परमाणु समझौता, NSG द्वारा कनाडा ऑस्ट्रेलिया आदि द्वारा हमारी नीति को उचित ही ठहरा रहे हैं।

अतः हमें पूर्ण निशस्त्रीकरण की हमारी नीति पर कायम रहना चाहिए तथा अभी हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए लेकिन हमें वैश्विक विश्वसनीयता को बढ़ाने हेतु और प्रयास करने चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. "Despite being set up more than a decade ago, Mekong- Ganga Cooperation has remained a non-starter." Do you agree? Give reasons for your answer. Discuss the potential of this cooperation for India.

"अपनी स्थापना के एक दशक से अधिक समय पश्चात् भी, मेकांग-गंगा सहयोग का आरम्भ नहीं हो सका है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए। भारत हेतु इस सहयोग की अन्तर्निहित संभावनाओं पर चर्चा कीजिए।

2000 में स्थापित मेकांग-गंगा सहयोग एशिया की दो बड़ी महत्वपूर्ण नदियों गंगा एवं मेकांग के बेसिन में अवस्थित भारत, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैण्ड का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। जिसमें पर्यटन, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं निहित हैं।

जहाँ तक सहयोग की बात है यह संगठन अभी तक पूर्णतः सफल नहीं कहा जा सकता है क्योंकि म्यांमा भी भारत का उत्तर क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंध में बहुत कम व्यापार होता है यदि हम ऐसा होने के कारणों की तरफ जाए तो हम पाते हैं कि उत्तर पूर्व भारत जो उत्तर क्षेत्र का प्रवेश द्वार हो सकता है वहाँ अभी भी ढाँचागत सुविधाओं का अभाव है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

म्यांमार लेकर प्रयत्न तक सैन्य शासन के अधीन, इन राष्ट्रों के आपसी विवाद भी इस तरह उचित क्रियान्वयन न होने के प्रमुख कारण रहे हैं। साथ ही इन लुक ईस्ट नीति पर भी व्यावहारिकता पर ज्यादा कार्य किया नहीं है परन्तु इन राष्ट्रों में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव है अतः भारत बौद्ध पर्यटन का केन्द्र बन सकता था लेकिन पर्यटन आंकड़े बताते हैं इस ऐसा नहीं हो पाए हैं।

जहाँ तक भारत के लिए निदानों की बात है पर निःसंदेह भारत के लिए आसियान का प्रवेश द्वार, ~~[illegible]~~ बौद्ध पर्यटन का केन्द्र बन सकता है भारत सरकार अभी चलाते यथा म्यांमार तेल एवं गैस पेपलाइन है साथ ही भारत का नवीनीकृत पिछड़ा क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्य निःसंदेह शामिल ने भारत के विकास का द्वार बन सकता है तथा इस

सहयोग निकाय को गैर-पारम्परिक मुद्दों यथा आतंकवाद, तस्करी, इत्यादि से निपट सकते हैं।

अतः भारत द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदम यथा कालादान मल्टीमॉडल प्रोजेक्ट, भारत-म्यांमार-थाईलैण्ड राजमार्ग, लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट की नीति की घोषणा से जारी डोनर आपसी द्वारा, जैसे सार्थक इन सब क्षेत्रों में आगे बढ़ा सकते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. The success of the India Africa Forum Summit as well as the future of India-Africa relations not only depends on India's ability to develop an attractive and sustainable approach to Africa, but also on the willingness of African leaders to look beyond Beijing when partnering up with foreign investors. Discuss.

भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन की सफलता और साथ ही साथ भारत-अफ्रीका के संबंधों का भविष्य न केवल अफ्रीका के लिए आकर्षक और संधारणीय दृष्टिकोण विकसित करने की भारत की क्षमता पर निर्भर करता है, वरन् विदेशी निवेशकों के साथ साझेदारी में अफ्रीकी नेताओं की बीजिंग से परे देखने की तत्परता पर भी निर्भर है। चर्चा करें।

हाल ही में दिल्ली में आयोजित भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन द्वारा लिए आशा की नई किरण लेकर सामने आया है। अफ्रीका के 54 राष्ट्रों में से उच्च राष्ट्रों अथवा नाइजीरिया, घाना, सरकारि की वृद्धि दर पिछला 8-10% तक रही है अतः भारत के लिए नए अवसर की तरह है लेकिन अफ्रीका के बदले में सभी राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा में भारत एवं चीन की प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण रही है।

चीन द्वारा अफ्रीका में व्यापक निवेश किया गया है चीन द्वारा ऊर्जा, खनन, आधारभूत क्षेत्रों में लगभग 90 मिलियन डॉलर का निवेश किया जा चुका है तथा चीनी तेल, गैस, कंपनियों द्वारा कर महत्वपूर्ण

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रोफेसर तीव्रता के साथ रखे हैं अतः मद्रीडी रावों का एक निश्चय प्रकाश भी ही छाया रहा है

इसी तरह भारत द्वारा अफ्रीका में अभी तक 20 अरब डॉलर का FDI निवेश किया गया है तथा भारतीय व्यापार भी 90 अरब डॉलर ही रहा है (चीन 200 अरब डॉलर) साथ ही भारत द्वारा अधिकतर निवेश क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास, शिक्षा लोकतांत्रिक मजबूती में किया गया है

अतः वास्तव में देखा जाए तो भारतीय निवेश गुणात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है साथ ही अफ्रीकी राष्ट्रों को दिल्ली सम्मेलन में दी गई रियायतें भी महत्वपूर्ण हैं।

लेकिन भारत अफ्रीकी निवेश बहुत हद तक अफ्रीकी नेताओं की सोच पर भी निर्भर है भारत गांधी नेहरू, गुट निरपेक्षता की वजह से अफ्रीका के हृदय निकट रहा है अतः

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सकारात्मक अफ्रीकी दृष्टिकोण से भविष्य में भारत अफ्रीकी संबंध को आगे बढ़ने की संभावना है जिससे भारत एवं अफ्रीकी राष्ट्रों ने महत्वाकांक्षाओं व आकांक्षाओं को पूरा करते हैं।